के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, एक योजना मंजूर की है जिसमें 10 मिलियन किलोग्राम सूत की आपूर्ति की जायेगी ।

(ङ) हथकरघा के विकास के लिए विभिन्न वर्तमान योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य को पर्याप्त सहायता दी गई है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	जारी की गई सहायता
1989–90	3191.32
1990–91	4499.84
1991–92	3769.42

सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत सूती कपड़ा मिलें

1066. **श्री अजीत सिंह :**
श्री राजूभाई एस० परमार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सूती कपड़ा मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या ये मिलें हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता रखती हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का आठवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में नई मिलें स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है । (नीचे देखिए))

(ख) चूंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में यार्न को लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों की मांग को, देश में कार्यरत समस्त कताई मिलों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन में से पूरा किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता,

(घ) जी नहीं,

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	सूती कताई मिलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
आसाम	1
बिहार	3
गुजरात	4
हरियाणा	1
जम्मू और कश्मीर	—
कर्नाटक	9
केरल	4
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	35
उड़ीसा	6
पंजाब	6
राजस्थान	3
तमिलनाडु	19
उत्तरप्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	1
पांडिचेरी (यू०टी०)	1
गोवा	—
हिमाचल प्रदेश	—
कुल योग :	115